



2026:AHC:65038

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 48537/2025

रोहित और 3 अन्य

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : निरज कुमार, राघवेंद्र प्रताप सिंह

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आरोपी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार और राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।

2. तत्काल आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत दिनांक 19.12.2024 के आरोप पत्र के तहत जो अपराध संख्या 0525/2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2), पुलिस स्टेशन- सौरीख, जिला- कन्नौज जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज की अदालत के समक्ष लंबित है जिसको रद्द करने और साथ ही 10.01.2025 के आदेश, जिसके

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



माध्यम से आवेदकों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए समन भेजा गया जिसको रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधी पक्ष संख्या 2, आवेदक संख्या 1 की पत्नी द्वारा उसके पति और ससुराल वाले, आवेदक संख्या 2 से 4 के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं। वह प्रस्तुत करता है कि मामला प्रकृति में वैवाहिक है। आरोप स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का है। 28.01.2026 के पूरक हलफनामे के पृष्ठ संख्या 6 पर एक समझौता है। वह हस्तक्षेप चाहता है।

4. राज्य के लिए विद्वान एजीए कोई आपति प्रस्तुत नहीं करते हैं यदि पक्ष दी गई परिस्थितियों में समझौता दायर करने के लिए विचारण न्यायालय से संपर्क करते हैं।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों में और (2012) 10 एससीसी 741** में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में अनुभव से यह टिप्पणी की कि वैवाहिक विवाद में होने वाले घरेलू झगड़े में परिवार के पूरे परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति है। इसके अलावा, **(2022) 6 एससीसी 599 में रिपोर्ट किए गए कहकशां कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखा है।

6. **नरेंदिरा कुमार और अन्य बनाम राज्य और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4048** में रिपोर्ट किए गए (प्रासंगिक पैराग्राफ 21) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 और आपराधिक प्रक्रियात्मक संहिता (528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 482 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सह-व्यापक शक्तियों पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार करते हुए। एक गैर-शमनीय अपराध में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के बिंदु पर, विशेष रूप से, वैवाहिक मामलों में, माननीय उच्चतम न्यायालय के पिछले निर्णयों पर विचार करते हुए, संविधान न्यायालयों में निहित अंतर्निहित शक्ति को पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते और समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए, जिसका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है।

7. क्या पक्षों (सूचक/पीड़ित और अभियुक्त) ने समझौता किया है, इस पर विचारण न्यायालय द्वारा सबसे अच्छा फैसला किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हो सकती हैं और तीस दिनों के भीतर पक्षों के बीच किए गए समझौते को दर्ज कर सकती हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल को अपने अभिलेख में रखेगा।

8. विचारण न्यायालय द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा यदि सूचक, पीड़ित और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और इसके सत्यापन के लिए अदालत के समक्ष पेश होते हैं। आपात स्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय अपने दिमाग को लागू करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

9. साठ दिनों की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा, यदि समझौता दायर किया जाता है और निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापित किया जाता है, अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण के साथ जारी रहेगा।

10. सभी पक्ष, जो समझौता दायर करते हैं और इसे सत्यापित करते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दायर करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528/482 के तहत आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

28/03/2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”